>

Title: Need to take urgent measures to check erosion of land and to provide funds for maintenance of watershed projects in hill states particularly in Uttarakhand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान पर्वतीय राज्यों विशेषकर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हो रहे भू-कटाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखण्ड में 88 प्रतिशत क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है जिसमें 35 प्रतिशत क्षेत्र चिंताजनक स्तर तक प्रभावित है। यदि इस चिंताजनक स्थिति को शीघ्र नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके भविष्य में भयानक परिणाम होंगे। भू-कटाव के कारण पर्वतीय जिलों पौड़ी एवं टिहरी से अधिक पलायन हुआ है जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि इन जिलों के निवासियों की जो संख्या 1971 में थी वही 2001 की जनगणना में सामने आई है। भू-कटाव के कारण कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है जोकि पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से ही कम है। भूस्खलन, खदानों का समाप्त होना, बादल फटने की घटनाओं से यह भू-कटाव हो रहा है। उत्पादकता को बचाने के लिए भू-कटाव को नियंत्रित करना आवश्यक है इसके लिए बड़े स्तर पर भू एवं जल संरक्षण को संवेदनशील क्षेत्रों में बचाने के लिए वाटरशेड प्रोग्रामों को बढ़ावा देना होगा। साथ ही इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर कोई फार्मूला तैयार करना होगा जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक ऋण दिलवाकर क्रियान्वित करवाया जा सके। उत्तराखण्ड में ही 1110 माइक्रो वाटरशेड हैं जिसमें से 322 के संरक्षण के लिए अभी तक कोई विशेष ग्रांट स्वीकृत नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस चिंताजनक गंभीर समस्या से पर्वतीय राज्यों को निजात दिलवाने के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए।